पीएम नेतन्याहू की खुली धमकी, कई और महीनों तक जारी रहेगा गाजा में हमास के साथ युद्ध

यरुशलम ।
हमास और इजराइल के बीच दो माह से अधिक समय से जंग जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो गई है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। वहीं, अब आतंकी समूह भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल न तो जंग की रफ्तार कम हो रही है और न ही लोगों की जान की परवाह की जा रही है। इस बीच, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र के साथ गाजा पट्टी की सीमा पर फिर से नियंत्रण करने का संकल्प लिया है। इससे हमलों में तेजी आ गई है।

सात अक्तूबर को हुआ हमला अब भी जारी

गौरतलब है, हमास ने गाजा से सात अक्तूबर को अचानक थोड़े-थोड़े अंतराल पर इजराइली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5,000 रॉकेट दाग दिए थे। यही नहीं, हमास के बंदूकधारी इजराइली शहरों में भी घुस आए थे और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर हमले किए थे। इस दौरान कई इजराइली सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया। इजराइल और फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध में अब तक 21000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास की तरफ से अचानक किए गए हमलों में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं, इजराइल की ओर से पलटवार में गाजा पट्टी से करीब 20,900 मौतों की जानकारी सामने आई है।

फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमारे कब्जे में हो

इजराइली पीएम नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मिस्र से सटे गाजा की सीमा के साथ लगने वाला फिलाडेल्फी कॉरिडोर बफर जोन या इसे सही ढंग से कहें दक्षिणी ठहराव बिंदु हमारे हाथों में होना चाहिए। इसे बंद किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई अन्य व्यवस्था उस विसैन्यीकरण को सुनिश्चित नहीं करेगी जो हम चाहते हैं। उन्होंने कहा, युद्ध अपने चरम पर है। हम सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं। जीत हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। जैसा कि इजराइली रक्षा बलों का कहना है कि युद्ध कई और महीनों तक जारी रहेगा।

ईरान को खुली धमकी

उन्होंने इजराइली-लेबनान सीमा पर लगभग हर दिन हो रही गोलीबारी को लेकर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला करने की धमकी दी। नेतन्याहू ने कहा, अगर हिजबुल्ला युद्ध को बढ़ाता है तो उसे ऐसे झटके झेलने पड़ेंगे, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा।

न्यूज ब्रीफ

आम चुनाव के लिए बांग्लादेश में सुरक्षा चाक-चौबंद, 1.89 लाख पुलिसकर्मी तैनात, निष्पक्ष मतदान पर जोर

ढाका । बांग्लादेश में सात जनवरी को होने वाले आगामी आम चुनाव को लेकर राजनीति दलों ने कमर कस ली हैं। सत्तारूढ़ समेत तमाम राजनीतिक दल लगातार लोगों को रिझाने के लिए सभा, रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच, मतदान से पहले पूरे बांग्लादेश में 1.89 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। विपक्षी दल बीएनपी के बहिष्कार के बीच होने वाले आम चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वर्तमान में देश के पुलिस बल में सिविल स्टाफ सहित लगभग 2.13 लाख कर्मचारी हैं। पुलिस मख्यालय में उप माहनिरीक्षक (ऑपरेशन) अनवर हुसैन ने कहा कि पूरे बांग्लादेश में कुल 1.89 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया हैं, जो मतदान के दिन मजिस्ट्रेटों के साथ चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्षेत्रों में गश्त भी लगाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 1.74 लाख पुलिसकर्मी बिना किसी छुट्टी के ड्यूटी पर रहेंगे, जबकि अन्य पुलिसकर्मी नियमित रुप से काम में लगेंगे। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा चुनाव बहिष्कार के चलते देशव्यापी हड़तालें, परिवहन नाकेबंदी का बीच-बीच में आह्वान किया जाता हैं। बीएनपी के मुताबिक, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के रहते कभी भी देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। पिछले दो माह में राजनीतिक हिंसा में 11 लोगों की मौत हो चुकी हैं और 386 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया हैं। राजनीतिक हिंसा में पुलिस ने कई विपक्षी कार्यकर्ताओं और हस्तियों को गिरफ्तार किया हैं, जिनमें बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीर शामिल हैं। बीएनपी लोगों से लगातार सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा करने का आह्वान कर रही हैं। साथ ही लोगों से करों और उपयोगिता बिलों का भुगतान न करने का आग्रह किया गया हैं।

भारी बारिश से ट्रेन की सुरंगों में भरा पानी, रेल सेवा रद्द होने से यूरोप आने-जाने वाले हजारों फंसे

लंदन । रेलवे सुरंगों में पानी भरने से ब्रिटेन-यूरोप के बीच चलने वाली यूरोस्टार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। नए साल के एक दिन पहले लंदन से पेरिस, ब्रूसेल्स और एम्स्टर्डम जाने वाली यात्राएं बाधित हो गई हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लंदन के पास ट्रैक में पानी आने से अस्थायी रूप में इन्हें बंद कर दिया गया है। दक्षिणी इग्लैंड के केंट में एब्सफ्लीट इंटरनेशनल स्टेशन के पास रेलवे टनल ने बाढ़ जैसी स्थिति बन गई हैं। इस दौरान स्टेशन में कई यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। यूरोप जाने वाली यूरोस्टार के अतिरिक्त यूके ट्रेन ऑपरेटर साउथवेस्टर्न रेलवे ने भी लंदन के सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन से अपनी हाई स्पीड सेवाओं को रद्द करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के मौसम कार्यालय ने कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी की है। दक्षिण ब्रिटेन में और वेल्स में पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही हैं कि जिसके कारण यात्रा में बाधाएं और सेवाओं रोकी जा सकती हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान पूरे वेल्स में बारिश का अनुमान जताया गया हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज करने की अपील, विपक्षी वकील ने कहा- अमेरिकी संविधान ने नहीं दी है इजाजत

वाशिंगटन । अमेरिका में इन दिनों राजनीतिक खींचतान जारी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अमेरिका के अभियोजकों ने संघीय अदालत से अपील की है कि वह ट्रंप के दावे को खारिज कर दें। ट्रंप ने अमेरिकी कानूनों का हवाला देते हुए दावा किया था कि 2020 के चुनावों में अपनी हार को पलटने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विशेष वकील जैक स्मिथ ने अदालत में तर्क दिया कि अमेरिकी संविधान और अमेरिका का कानून पूर्व राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए की गई कार्रवाई के लिए आपराधिक आरोपों से पूर्ण छूट देने का समर्थन नहीं करता। राष्ट्रपतियों को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। वहीं, ट्रंप के वकीलों ने 23 दिसंबर को दायर याचिका में कहा है कि आधिकारिक जिम्मेदारियों से संबंधित आचरण के लिए आरोप लगाना राष्ट्रपति पद को कमजोर बनाता है। नौ जनवरी को तीन न्यायाधीशों की एक बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि अमेरिका में साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी।

इमरान ने पाकिस्तान को 157 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया

जांच रिपोर्ट में दावा- सिर्फ 9 करोड़ देकर 316 करोड़ के गिफ्ट रख लिए

इस्लामाबाद ।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महज 9 करोड़ रुपए (पाकिस्तानी करंसी) देकर सरकारी खजाने (तोशाखाना) से 316 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स अपने पास रख लिए थे। खान और उनकी पत्नी बुशरा ने मिलकर पाकिस्तान के खजाने को मोटे तौर पर 157 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के टीवी चैनल ने यह जानकारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से दी है। खास बात ये है कि ये सिर्फ उन गिफ्ट्स की डीटेल्स हैं, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को दी थीं। बाकी जानकारी आना बाकी है।

क्या कहती है एंटी करप्शन यूनिट एनएबी की रिपोर्ट - तोशाखान गिफ्ट केस में इमरान के साथ उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं। इमरान को तो इस केस के एक मामले में सजा भी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक- इमरान बतौर प्रधानमंत्री जब भी सऊदी अरब दौरे पर गए तो क्राउन प्रिंस और सऊदी सरकार ने उन्हें महंगे तोहफे दिए। सऊदी रॉयल फैमिली पहले भी अपने देश की ऑफिशियल विजिट पर आने वाले मेहमानों को महंगे तोहफे देती रही है। बहरहाल, इमरान को सिर्फ सऊदी अरब से मिले तोहफों की कीमत एनएबी ने 316 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आंकी है। इमरान और बुशरा ने सरकारी नियमों को दरकिनार करके सिर्फ 9 करोड़ रुपए देकर ये गिफ्ट्स अपने पास रख लीं। रिपोर्ट में कहा गया- जांच में पता चला कि इन गिफ्ट्स की सही कीमत आंकने (प्रॉपट एसेट्स वैल्यूशन) का कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया। जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से इनकी कीमत आंकी गई तो यह 316 करोड़ पाकिस्तानी रुपए निकली। सिर्फ अंदाजे से इनकी कीमत 18 करोड़ रुपए बता दी गई। करप्शन की इंतेहां देखिए कि इमरान-बुशरा ने महज 9 करोड़ देकर ये गिफ्ट्स अपने पास रख लिए।

रिपोर्ट में झोल - रिपोर्ट में एक चीज बिल्कुल साफ नहीं है। दरअसल, ये रिपोर्ट कहती है कि इमरान और बुशरा ने मिलकर पाकिस्तान के सरकारी खजाने को 157 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। सवाल ये है कि अगर 316 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स 9 करोड़ रुपए में खरीदे गए तो नुकसान 157 करोड़ रुपए का कैसे हुआ ऐसा लगता है कि रिपोर्ट में उस विवादित नियम के हिसाब से कैल्कुलेशन किया गया है, जिसके तहत टोटल वैल्यूएशन का 50 प्रतिशत देकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देशों से मिले तोहफों को अपने पास रख सकते हैं। एनएबी इस बारे में जल्द ही बयान जारी कर सकती है। दूसरे देशों में फाइनेंशियल क्राइम की जांच करने वाली एजेंसी एफबीआर तो इन गिफ्ट्स का वैल्यूएशन ही नहीं कर पाई। उसने कहा- जिस कंपनी ने यह तोहफे तैयार किए, वो फिलहाल एक्टिव नहीं है। एक एक्सपर्ट इमरान बशीर ने कहा- अगर 316 करोड़ रुपए इन गिफ्ट्स की वास्तविक कीमत है तो इमरान-बुशरा 157 करोड़ रुपए देकर ही ये तोहफे अपने पास रख सकते थे। लेकिन, उन्होंने सिर्फ 9 करोड़ ही चुकाए। रिपोर्ट में कहा गया- तोशाखाना के किसी अफसर या कर्मचारी को दोषी ठहराने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश का वो विरोध नहीं कर सकते थे।

अब तोशाखाना केस को बारीकी समझिए - चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी। अब एनएबी की रिपोर्ट में ये तमाम आंकड़े भी झूठ साबित हो गए हैं। करीब 3 साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते। पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। तोहफे की अनुमानित कीमत अगर 10 हजार से ज्यादा है तो 20 प्रतिशत कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है।

इजराइली मीडिया का दावा

युद्ध में अब तक गाजा के 70 प्रतिशत घर और इमारत तबाह इजराइल ने बताया यह कारण

तेल अवीव ।
इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इजराइली सेना और हमास आतंकी लगातार एक-दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। इस बीच, इजराइल की एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि युद्ध में अब तक गाजा के लगभग 70 प्रतिशत घर और इमारतें तबाह हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा ताजे सेटेलाइट तस्वीर और अन्य रिमोट सेंसिंग तरीकों के विश्लेषण के हवाले से किया गया है है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इमारतों में फैक्ट्रियां, प्रार्थना स्थल, स्कूल, शॉपिंग मॉल और होटल शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गाजा के 36 अस्पतालों में से केवल आठ अस्पताल ही मरीजों को स्वीकार कर पा रहे हैं। बाकि अस्पतालों में पानी, बिजली और संचार सहित अन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। वहीं, शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट पेप का कहना है कि ड्रेसडेन और बमबारी वाले शहरों की सूची में अब गाजा का नाम भी शामिल हो जाएगा। इजराइली वायुसेना और इजराइली जमीनी सेना गाजा में लगातार हमले कर रहे हैं। गाजा में इजराइली सेना ने कई आतंकी गुर्गों को मार गिराया है। नए सेटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद इजराइल ने बताया कि हमास के आतंकी गाजा के स्कूलों, प्रार्थना स्थलों और अस्पतालों सहित अन्य इमारतों में छिपे हुए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में इजराइली सेना के हमले में 165 फलस्तीनी लोगों की मौत हो गई। जबकि, 250 लोग घायल हुए। इजराइल ने वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 14 लोगों को हिरासत में लिया है। सात अक्तूबर से अब तक इजराइली हमलों में कम से कम 21,672 फलस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है और 56,165 लोग घायल हैं। वहीं, अब तक आंतकियों के हमलों में 1139 इजराइली लोगों की मौत हुई है। हमास ने कहा कि ये यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने कहा कि इजराइली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंक इसे अपवित्र किया था।

तीन और सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा उत्तर कोरिया, किम जोंग की चाहत दक्षिण कोरिया पर कब्जा

प्योंगयांग ।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अगले साल तीन और सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। यह खबर सामने आई है। बीते महीने ही उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक अपनी पहली सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी। अपनी सेना को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया इन सैन्य जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। किम जोंग उन ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी की पांच दिवसीय बैठक के दौरान यह लक्ष्य रखा। बीते महीने उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने अपनी टोही सैन्य सैटेलाइट से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य ठिकानों की तस्वीरें ली हैं। बीती 21 नवंबर को उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य जासूसी सैटेलाइट मलिंगयॉन्ग-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। इससे पहले मई और अगस्त में इसकी कोशिश विफल रही थी। इस सफलता से उत्साहित किम जोंग उन ने अगले साल तीन और सैन्य जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार, किम जोंग उन ने बैठक के दौरान कहा कि हमें परमाणु खतरे पर तुरंत

प्रतिक्रिया देनी चाहिए और परमाणु बल समेत सभी भौतिक बलों को जुटाकर अपनी तैयारियों को बेहतर करने की जरूरत है ताकि पूरे दक्षिण कोरिया को अपने नियंत्रण में किया जा सके।

कोरियाई तानाशाह ने अनमैन्ड आर्म्ड एरियल व्हीकल को भी विकसित करने की जरूरत बताई। किम ने कहा कि वह कोरिया को अब एकजुट करने पर सहमत नहीं हैं और दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया से एकीकरण अब संभव नहीं है। इससे साफ है कि दोनों देशों के रिश्ते इस साल भी तनावपूर्ण रह सकते हैं। उत्तर कोरिया अपने परमाणु मिसाइलों के विकास पर फोकस कर रहा है। किम ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो हम परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेंगे।

पाकिस्तान के दामन पर एक और दाग, जबरन गायब किए गए लोगों का आंकड़ा तीन हजार के पार पहुंचा

इस्लामाबाद ।
पाकिस्तान में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। अब एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान को फिर आईना दिखाया है। दरअसल पाकिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों का आंकड़ा तीन हजार के पार पहुंच गया है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक गैर सरकारी संगठन है, जो पाकिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों के आंकड़े जुटाता है।

गायब लोगों की रिकवरी की स्थिति बेहद खराब

इस संगठन ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 तक पाकिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों का आंकड़ा 3120 हो गया है। साल 2023 में जबरन गायब किए गए लोगों के 51 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार, गायब हुए लोगों के परिवारों की काउंसिलिंग कराई गई लेकिन इनकी संख्या महज 120 है। जबरन गायब हुए आठ लोगों के मामले पाकिस्तान के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गायब हुए लोगों के मामलों में विभिन्न अदालतों ने सकारात्मक आदेश दिए हैं

लेकिन अभी भी गायब हुए लोगों की रिकवरी की स्थिति बेहद खराब है।

पाकिस्तानी सेना पर भी बलूचिस्तान में लगते रहे हैं गंभीर आरोप

गायब हुए लोगों में पत्रकार, छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन डीएचआर ने गायब हुए 69 बलोच छात्रों के मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी उठाया है। इस पर पाकिस्तान की सरकार ने बताया है कि गायब हुए बलोच छात्रों में से 22 छात्रों का पता चल गया है लेकिन 28 अभी भी गायब हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसकी वजह से वहां पाकिस्तानी सेना लोगों पर जुल्म करती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लोगों को जबरन गायब करने और उनके फेक एनकाउंटर करने के आरोप लगते रहते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को पुतिन ने दी नए वर्ष की शुभकामनाएं, कहा- भारत-रूस लगातार आगे बढ़ रहे

मॉस्को ।
2023 के अंतिम दिन रूस के राष्ट्रपति ने भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने जोर दिया कि वैश्विक परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हो गई हैं, बावजूद इसके रूस और भारत के बीच संबंध आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद रूस और भारत के बीच जारी साझेदारी गतिशील रूप से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन और नई दिल्ली में आयोजित जी20 में भारत के कदम की सराहना की। उन्होंने भारत की अध्यक्षता की भी प्रशंसा की।

उन्होंने विश्वास जताया कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। तीन दिन पहले, पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण तरीकों से

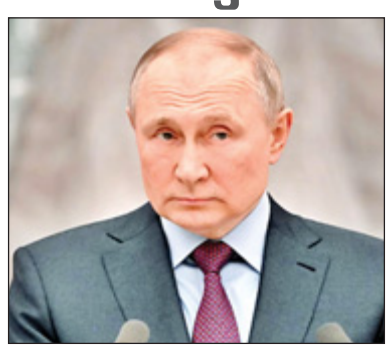

रूस-युक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मोदी के रूख को समझते हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार-बार उल्लेख किया। मुझे पता है कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को शांति से हल किया जा सके।

हम इस पर गहराई से बात करेंगे। उन्होंने भारत-रूस संबंधों के लिए आभार व्यक्त किया है। हम दोनों विकास के नए आयाम छू रहे हैं। पिछले साल की तुलना में हमने विकास दर को पछाड़ दिया है। हम अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। पुतिन ने भारत और रूस की साझेदारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में एक साथ हैं। हम पेट्रोल के साथ-साथ उच्च तकनीकी क्षेत्र में भी साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनावों के लिए भी बधाई दी थी।

उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से हमें बेहद खुशी मिलेगी। हम इस दौरान कई संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जयशंकर से कहा कि आप पीएम मोदी को बताएं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं कामना करता हूं कि वह जल्द ही रूस आएं। मुझे पता है कि पीएम मोदी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के कारण काफी व्यस्त हैं। मैं उनकी सफलता के लिए कामना करता हूं।

इसी महीने की शुरुआत में पुतिन ने कहा था कि मैं भारत या भारतीय लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर कर सकने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि मैं जानता हूं कि उन पर ऐसा दबाव है। मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। ईमानदारी से कहूं, तो मैं कभी-कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर मोदी के सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि रूस व भारत के रिश्ते सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी मुख्य गारंटी पीएम मोदी की नीति ही है। पीएम मोदी भारत के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं।

ब्रिक्स में अब शामिल नहीं होगा अर्जेंटीना, नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने लिया निर्णय

ब्यूनस आयर्स । पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने के अपने अभियान के वादे को पूरा करते हुए, माइली ने 22 दिसंबर को एक पत्र लिखा, लेकिन इसे अब जारी किया। माइली ने रूस, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीकी नेताओं को लिखा, वह एक ऐसी विदेश नीति अपनाएंगे जो पश्चिमी देशों के साथ संरेखित हो व आगे बढ़े। अब ब्रिक्स में 11 के बजाय 10 देश होंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव अभियान में ही ब्रिक्स को वामपंथियों का संगठन कहते हुए इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हमारा जियोपॉलिटिकल गठबंधन अमेरिका व इजराइल के साथ है। हम कम्युनिस्टों (ब्रिक्स) के साथ नहीं जुड़ेंगे। यह फैसला चीन, भारत व अन्य ब्रिक्स देशों को झटका है। अर्जेंटीना में अलबर्टो फर्नांडीज की सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला लिया था।